

# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 30/2022  
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/50

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

पीरामल केपीटल एण्ड हाउसिंग  
फायर्नेस. लिमिटेड, शाखा उदयपुर

अप्रार्थी / रेस्पोंडेंटस:-

1. फरीद अहमद पुत्र जमील अहमद निवासी  
वार्ड नं. 01 उदा जी का गढ़ा, खमेरा गढ़ा  
घाटोल जिला बांसवाड़ा
2. शबनम आरा पत्नी फरीद अहमद निवासी  
मुकाम पोस्ट खमेरा, तहसील घाटोल,  
जिला बांसवाड़ा

बनाम


निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति  
हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 14.09.2022

पीरामल केपीटल एण्ड हाउसिंग फायर्नेस. लिमिटेड, शाखा उदयपुर ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 1. फरीद अहमद पुत्र जमील अहमद निवासी वार्ड नं. 01 उदा जी का गढ़ा, खमेरा गढ़ा घाटोल जिला बांसवाड़ा 2. शबनम आरा पत्नी फरीद अहमद निवासी मुकाम पोस्ट खमेरा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (ऋणी/अप्रार्थीगणों) को दिनांक 31-07-2018 को 20,17,331 (बीस लाख सत्रह हजार तीन सौ इकत्तीस रुपया) ऋण राशि स्वीकृत की थी। अप्रार्थीगण नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 11-03-2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगणों के खाते दिनांक 31-03-2021 को कुल बकाया राशि मय ब्याज 21,26,196 रु. (इक्कीस लाख छब्बीस हजार एक सौ छियानवे) बकाया है, उक्त राशि एवं तत्पश्चात ब्याज व खर्च आदि सहित राशि के भुगतान के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। अप्रार्थी ने ऋण राशि व उसके ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति को रहन किया जिसके अन्तर्गत श्रीमती शबनम आरा पत्नी फरीद अहमद निवासी मुकाम पोस्ट खमेरा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा की सम्पत्ति आवासीय मकान वाके आराजी नंबर 326, ग्राम भुंगडा, तहसील घाटोल, बांसवाड़ा मय समस्त पार्ट एवं पार्सल बैंक में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार क्षेत्रफल 1258 वर्ग फिट है। जिसके पूर्व में बानी आपा का मकान, पश्चिम में वहीद खा का मकान, उत्तर में जफरुल्लाखों का मकान एवं दक्षिण में 10 फीट का आम रास्ता स्थित है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा



  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बांसवाड़ा (राज.)



(व) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ किया गया

गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

राष्ट्रीय आवास बैंक के पंजीकरण प्रमाण पत्र सं. 01.0014.01 दिनांक 31.07.2001 से 1967 के राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम की धारा 29ए के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक को पदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीवान हाउसिंग फाइनांस कारपोरेशन लिमिटेड को आवास वित्त संस्थान का व्यापार करते रहने के लिये पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, भारत सरकार द्वारा जारी नाम परिवर्तन के अनुसार निगमन का प्रमाण पत्र (कम्पनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 29 के अनुसार) दिनांक 03.09.2021 अनुसार कंपनी का नाम दीवान हाउसिंग फाइनांस कारपोरेशन लिमिटेड से बदल कर पीरामल कंपनी लिमिटेड हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड कर दिया गया है। प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु वित्तीय संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 12-05-2021 को ऋणी अप्रार्थीगणों को नोटिस दिया गया जिस पर अप्रार्थीगणों/ऋणी ने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व न ही ऋण राशि जमा नहीं करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 31-07-2018 को 20,17,331 (बीस लाख सत्रह हजार तीन सौ इकत्तीस रुपया) ऋण स्वीकृत किया गया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 07-07-2022 को जारी किये। अप्रार्थीगणों के नोटिस दिनांक 20-07-2022 को बाद तामील प्रस्तुत हुए किन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। न्यायहित में अवसर दिये जाने के उपरांत भी आज पेशी दिनांक 14-09-2022 तक भी अप्रार्थीगण स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। बार बार रुक रुक कर अप्रार्थीगणों को सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई गई, अप्रार्थीगण स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अप्रार्थीगणों को समुचित अवसर प्रदान करने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किया एवं अनुपस्थित है। अप्रार्थी का जवाब बंद किया जाता है एवं एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।





क्लर्क एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बांसवाड़ा (राज.)

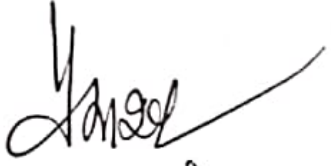
(व) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ किया गया।  
4. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ किया गया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तीय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार घाटोल को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात पीरामल केपीटल एण्ड हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, शाखा उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



  
(प्रकाश चन्द्र शर्मा)  
क्लर्क एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
बासवाड़ा (राज.)  
बासवाड़ा

श्री पंकज पारगी Adv.